"विकसित" भारत के लिए कृषि नीति और बजटीय पुनर्संरचना

प्रो. वी. पद्मानंद

पार्टनर और कृषि उद्योग नेता,
ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग, ग्रांट थॉर्नटन, भारत

भारत, कृषि, बागवानी, मसालों और मसालों, दूध, अंडे और मछली के उत्पादन में विश्व में अग्रणी होने के बाद भी, विश्व निर्यात में इसका भाग बहुत कम है, जो कि मात्र 6.84 प्रतिशत है। उत्पादकता और उपज प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तुलना में एक तिहाई से भी कम है, और अधिकांश वस्तुओं में घरेलू बाजार उच्च टैरिफ दीवारों द्वारा संरक्षित है। गैर-प्रतिस्पर्धात्मकता का यह परिदृश्य चिंता का विषय है। इसके अलावा, कृषि और बागवानी उत्पादन का अधिकांश भाग (लगभग 10 प्रतिशत) कटाई के बाद, प्रसंस्करण और रसद मूलभूत संरचना से संबंधित अंतराल के कारण नष्ट हो जाता है। साथ ही, यह क्षेत्र आर्थिक रूप से आकारहीन और खंडित भूमि जोत के साथ-साथ वर्षा आधारित खेती पर अत्यधिक निर्भरता के मामले में बाधाओं से घिरा हुआ है। इस परिदृश्य में, नीति को उत्पादकता वृद्धि और कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने, वैश्विक बाजारों में पैठ बढ़ाने और साथ ही किसानों की आजीविका और समावेशी विकास में योगदान के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि (और संबद्ध गतिविधि) क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

बीज, कीटनाशकों, उर्वरक, पशु चारा इनपुट के साथ-साथ पर्याप्त सलाहकार और विस्तार

सेवाओं से संबंधित गुणवत्ता इनपुट तक पहुंच सुनिश्चित करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इस संदर्भ में एफपीओ सुविधाजनक सुविधा मंच के रूप में भी काम कर सकते हैं। वाटरशेड विकास, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, कृषि मशीनीकरण, सौर/विद्युत बाड़ (बागवानी उत्पादों के लिए), और कटाई के बाद की सुविधाएं अन्य आवश्यक मूलभूत संरचना और महत्वपूर्ण निवेश विकल्प हैं। ये पहल सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र के योगदान को कम से कम 30-40 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं।

हालांकि, बजट का संबंधित कृषि (और संबद्ध गतिविधियाँ) घटक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के साथ प्रयोज्य आय बढ़ाने, उर्वरक इनपुट पर सब्सिडी देने और एमएसपी की प्रस्ताव करने पर केंद्रित है। वास्तव में, 5.3 लाख करोड़ रुपये के संबंधित बजटीय परिव्यय में से केवल 20,000 करोड़ रुपये ही उत्पादकता बढ़ाने वाले मूलभूत संरचना और निवेश की ओर उन्मुख हैं। लगभग 40,000 करोड़ रुपये कृषि गतिविधियों के लिए ऋण और बीमा पर परिव्यय है। उल्लेखनीय रूप से, चीन जैसे देशों में उत्पादक निवेश में संबंधित परिव्यय इस क्षेत्र पर बजटीय व्यय का 14 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए देश के लिए वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) में निवेश की दक्षता बढ़ाने के लिए बजटीय और योजना परिव्यय को फिर से उन्मुख करने की आवश्यकता है। आईसीओआर मूल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निवेश में दिए गए वृद्धिशील परिवर्तन के लिए उत्पादन में वृद्धिशील परिवर्तन को दर्शाता है। इससे भारत को संभवतः 2047 से पहले ही विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, और आर्थिक सर्वेक्षण में परिकल्पित 8 प्रतिशत और उससे अधिक प्रति वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर को प्राप्त करना कठिन है। उत्पादकता बढ़ाने वाले विकल्पों में निवेश

बढ़ने से निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और साथ ही जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान भी बढ़ेगा और आईसीओआर को मौजूदा 4.5 से अनुकूल रूप से कम करके 'विकसित भारत' का पद प्राप्त किया जा सकेगा। अनिवार्य रूप से, भारत को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित भारत की साख को दो दशक या उससे भी कम समय में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय को 2900 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 30,000 अमेरिकी डॉलर करने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू निवेश (जीडीआई) को जीडीपी के अनुपात में वर्तमान में लगभग 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। वैकल्पिक रूप से, या पूरक रूप से, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश की दक्षता ही विकास प्रक्षेपवक्र को पूरक बनाएगी।

जबकि सरकार में नीति निर्माता निवेश-चालित विकास की क्षमता को समझते हैं, बजटीय आवंटन स्पष्ट रूप से वैकल्पिक उपभोग-चालित विकास की ओर झुकाव को दर्शाता है। बजट में व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) स्लैब में वृद्धि के माध्यम से शहरी मध्यम वर्ग के हाथों में अतिरिक्त प्रयोज्य आय के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था भी इसी तरह की एक पहल है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 63,500 करोड़ रुपये का खर्च इस पहल को और बढ़ाता है। चिंता मूलभूत संरचना पर खर्च में निवेश प्रोत्साहन और उत्पादकता बढ़ाने वाले विकल्पों के क्षेत्र-स्तर पर कार्यान्वयन को बढ़ाने पर आवश्यक खर्च को कम करने की है। भारत में बचत और निवेश गुणक लगभग 3.3 पर निश्चित रूप से उपभोग खर्च को बढ़ाएगा। हालांकि, चिंता भौतिक, तकनीकी, साथ ही रसद मूलभूत संरचना में निवेश से आने वाले दीर्घकालिक विकास के विकल्प को कम करने की है। इस संदर्भ में विकास के लिए दीर्घकालिक प्रोत्साहन दुर्भाग्य से देखा जाता है। इसलिए, नीति और बजटीय परिव्यय के उचित पुनः उन्मुखीकरण की उत्तरोत्तर आवश्यकता है।